PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Sanmarg (सन्मार्ग)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

15वें वित्त आयोग ने राज्य में ऋण की अधिकता को बताया गंभीर मुद्दा

आयोग की बैठक से आशावादी हुई सीएम, विकासकार्यों की आयोग अध्यक्ष ने की प्रशंसा

कोलकाता : राज्य में आर्थिक परिस्थितियों का जायजा लेने आये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने बंगाल पर ऋण की अधिकता को एक गंभीर मुद्दा बताया। मंगलवार को नवान्न सभागार में सीएम ममता बनर्जी के साथ हुई बैठक के बाद एन के सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य पर ऋण का बोझ 3.40 लाख करोड़

- कहा : नौकरी के अवसर से लेकर ई-परिसेवा में बंगाल का प्रदर्शन सराहनीय

रुपये है जो अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है। संभव है यह राशि राज्य को विकासमूलक कामों को गति देने में बाधा पहुंचाती होगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आयोग के सदस्य इस जटिल समस्या के बारे में केंद्र को अवगत कराएंगे। इधर राज्य सरकार की ओर से भी आयोग को ऋण की अधिकता और क़र्ज में रियायत करने का प्रस्ताव दिया है।

नवान्न में 15वें वित्त आयोग की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह और राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्र

आयोग की बैठक से आशावादी हुईं सीएम

आयोग के साथ हुई बैठक से सीएम आशावादी हुई और कहा कि बैठक में राज्य ने अपनी समस्याओं को बारीकी से राज्य को बताया है।

नौकरी के अवसर से लेकर ई-परिसेवा में बंगाल का प्रदर्शन सराहनीय

आयोग ने कहा कि पिछले कुछ सालों पर नजर दौड़ाएं तो देखा जा रहा है कि यहां नौकरी के अच्छे-खासे अवसर दिए गए हैं। दूसरी तरफ सरकार द्वारा चालू की गयी ई-परिसेवा से सरकारी कामों में पारदर्शिता बरती जा रही है, इससे राज्य के विकास की गतिं और तेज होगी।

उम्मीद है आयोग इसे समझेगा और राज्य पर कर्ज का जो बोझ है उसे कम करने की तरफ कोई उपाय निकालेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सभी क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करता आया है बावजूद इसके केंद्र से सहायता नहीं मिलती है। इस बैठक के बाद शायद कोई नया रास्ता खुले।

मुख्यमंत्री ने आयोग के समक्ष विभाजन वाले अप्रत्यक्ष क़रों में राज्य की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की।

ऋण के बोझ के बाद बावजूद राज्य में जीडीपी ग्रोथ बढ़ा

ऋण का बोझ होने के बावजूद एन के सिंह ने पिछले कुछ सालों में राज्य ने जीडीपी ग्रोथ में जिस तरह बढ़ोतरी की है उसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच ही राजस्व में भी अच्छी-खासी बढ़त हासिल की है।

कई क्षेत्रों में राज्य का रहा है बेहतरीन प्रदर्शन

आयोग अध्यक्ष ने राज्य के कार्यों की सराहना की और कहा कि राज्य का कई क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य बाकी के राज्यों की तुलना में बेहतर देखा जा रहा है।

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Prabat Khabar (प्रभात खबर)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

बंगाल सरकार की पहल से बढ़ेंगे रोजगार के मौके : वित्त आयोग

- **वित्त आयोग ने माना कि कर्ज के कारण प्रभावित हो रही हैं योजनाएं**

पत्रकारों से बातचीत करतीं सीएम ममता बनर्जी. साथ में वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गयी पहल व योजनाओं से राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति हो रही है. राज्य सरकार की पहल से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. बंगाल सरकार ने पिछले चार-पांच वर्षों में अर्थ-व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है. यह बातें मंगलवार को 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने नवान्न सभाकक्ष में संवाददाता सम्मेलन में कही.

गौरतलब है कि मंगलवार को राज्य सचिवालय के पास बने नवान्न सभाकक्ष में 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाओं की समीक्षा व क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने आयोग के समक्ष वाम मोरचा के शासनकाल के दौरान लिये गये कर्ज से उबारने की बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग के चेयरमैन और आयोग के सदस्यों के साथ बैठक काफी अच्छी रही. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 15वें वित्त आयोग में पश्चिम बंगाल को अधिक राशि आवंटित की जायेगी.

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री सिंह ने राज्य सरकार के विभिन्न आर्थिक सुधारों की सराहना की. जिसमें कर संरचना में सुधार, आंतरिक औसत उत्पादन में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और ऑनलाइन कर संग्रह प्रणाली शुरू करना शामिल है. उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थायी लाभ देगी.उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार की भूमिका की सराहना की.

राज्य की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत की जाये : ममता

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को 15वें वित्त आयोग की बैठक के दौरान आयोग के समक्ष विभाजन वाले अप्रत्यक्ष करों में राज्य की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की. साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही और राज्य सरकार को उम्मीद है कि आयोग कर्ज पुनर्गठन प्रस्ताव पर विचार करेगा. साथ ही उन्होंने वित्त आयोग से टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) को नहीं लागू करने की सिफारिश की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2011 की जनगणना के आधार पर केंद्रीय कोष का वितरण करके आबादी नियंत्रण में आगे रहने वाले राज्यों को दंडित करना उचित नहीं होगा. हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम न्याय हासिल करने तक संघर्ष करेंगे. इससे साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग से कहा है कि केंद्र सरकार अगर कोई योजना शुरू करना चाहती है, तो वह इसके बारे में राज्यों को भी पहले से जानकारी दे. ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार योजनाएं शुरू कर, उसे राज्यों पर थोप दे. मुख्यमंत्री ने एक बार फिर वाममोर्चा कार्यकाल के दौरान लिये गये ऋण का पुनर्गठन करने या उसमें छूट देने का आवेदन किया. मुख्यमंत्री के इस आवेदन पर वित्त आयोग के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के कर्ज के मुद्दे को गंभीरता से लिया है. आयोग ने कहा कि उसे जो अधिकार मिले हैं, उसके अंतर्गत इस मुद्दे के हल के लिये विभिन्न विकल्पों को तलाशेगा ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका अंतहीन प्रभाव नहीं रहे. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के ऊपर 3 .40 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. राज्यों के बीच यह कर्ज सर्वाधिक है.

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Dainik Jagoan (दैनिक जागरण)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 19/07/2018

वित्त आयोग ने कर्ज का बोझ कम करने का दिया आश्वासन

आयोग ने की ममता सरकार की सराहना, प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री की हुई अहम बैठक

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: 15 वें वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के आर्थिक सुधारों जैसे राजस्व वसूली में वृद्धि और आनलाइन के जरिए कर संग्रह आदि के प्रयासों की सराहना की है। नवान्न में मंगलवार को वित्त आवोग के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हुई बैठक के बाद आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार के आर्थिक सुधार से राजस्व उगाही और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। राज्य सरकार के आर्थिक सुधार के तहत उठाए गए कदम जीडीपी बढ़ने में भी सहायक है। सरकार ने कर्ज का पुनर्गठन करने के लिए आयोग को ज्ञापन दिया है। राज्य पर कर्ज का बोझ कम करने के प्रयासों पर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। राज्य के विकास में कर्ज

बैठक में एनके सिंह से गुफ्तगू करतीं ममता बनर्जी • जागरण

बाधक न बने इसको ध्यान में रखकर वित्त आयोग गंभीरता से विचार करेगा।

सिंह ने कहा कि वित्त प्रबंधन के युक्तिसंगत नये उपाय करके राज्य सरकार ने राजस्व उगाही में तथा कर संग्रह में वृद्धि की सफलता प्राप्त की है। इससे पिछले कुछ वर्षों में जो जीडीपी बढ़ा है वह सराहनीय है। सरकार ने विरासत में मिले भारी कर्ज के बोझ की ओर आयोग का ध्यान खींचा है। उन्होंने सरकार को आश्वस्त किया किया कि इस मुद्दे के समाधान हेतु 15 वें वित्त आयोग ऐसे उपाय करेगा कि कर्ज का बोझ राज्य की वित्तीय प्रगति में बाधक नहीं बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडलों से हुई सकारात्मक बातचीत के आधार पर आयोग बंगाल के लिए अल्पावधि व दीर्घावधि सुधारों के प्रति तत्पर रहेगा।

संवाददाता सम्मेलन में सिंह के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के वित्तमंत्री, अमित मित्रा तथा वित्त आयोग के अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग के चेयरमैन के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत हुई। राज्य पर भारी कर्ज के बोझ को पुनर्गठन करने के लिए उन्होंने वित्त आवोग को ज्ञापन दिया है।

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Rajasthan Patrika (राजस्थान पत्रिका)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

राज्य सचिवालय नवान्न के सभागार में मंगलवार को वित्त आयोग की दूसरे दिन की बैठक में आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा विचार-विमर्श करते हुए।

बंगाल के ऋण पुनर्गठन की मांग पर होगा विचार- वित्त आयोग

ममता बनर्जी ने जताया विश्वास

कोलकाता. राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, राजनीतिक दलों के साथ दो दिन से जारी मैराथन बैठक के बाद 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने राज्य के ऋण के पुनर्गठन संबंधी मांग पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया। हावड़ा स्थित राज्य सचिवालय नवान्न के सभागार में आयोग की बैठक के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोग के चेयरमैन एनके सिंह से मुलाकात की और बंगाल के ऋण का पुनर्गठन करने की मांग की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में एनके सिंह ने कहा कि बंगाल सरकार ने अपने ऋण के पुनर्गठन किए जाने की जरूरत जोरदार तरीके से पेश की है। आयोग मुख्यमंत्री की मांग पर गंभीरता से विचार करेगा, जिससे सरकार को जन कल्याण योजनाओं पर खर्च करने के पैसे मिल सकें। राज्य सरकार ने पहले ही आयोग को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिससे आयोग मांगों को बेहतर तरीके से समझ सका है।

बंगाल पर वर्तमान में 3 लाख 64 हजार 016 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में बढ़ कर 3 लाख 94 हजार 832 करोड़ हो जाएगा। इससे पहले बैठक में मुख्यमंत्री ने आयोग को बताया कि वर्ष 2011 में सत्ता में आने पर उनकी सरकार को राज्य पर 2 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला था। सरकार को इस साल 47 हजार 719 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2017-18 में 47 हजार 272 करोड़ रुपए कर्ज चुकाना पड़ा था। सरकार ने इस साल 27 हजार 136 करोड़ रुपए सूद के ही चुकाए हैं।

सिंह ने संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आयोग मानता है कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था ने कर राजस्व बढ़ाने के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। बैठक को सार्थक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि आयोग कर्ज पुनर्गठन प्रस्ताव पर विचार करेगा। मुख्यमंत्री ने आयोग के समक्ष विभाजन वाले अप्रत्यक्ष करों में राज्य की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग भी की।

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Salamduniya (सलामदुनिया)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठक में वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने कहा

ऋण पुनर्गठन पर विचार करेगा आयोग

- शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा में बंगाल है उदाहरण
- बैठक में हर पहलू पर हुई बात : ममता

संवाददाता, सलाम दुनिया

नवान्न में वित्त आयोग के चेयरमैन एन. के. सिंह के साथ बात करतीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व वित्त मंत्री अमित मित्रा

कोलकाता : राज्य सचिवालय नवान्न में मंगलवार को 15वें वित्त आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा, वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह सहित वित्त आयोग का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिदल शामिल था। बैठक खत्म होने के बाद आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के साथ हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पर लदे ऋण को लेकर वित्त आयोग से ऋण का पुनर्गठन करने का अनुरोध किया जिस पर आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने विचार करने का आश्वासन दिया। सिंह ने कहा कि आयोग अपनी सीमा के तहत राज्य सरकार की सभी माँगों पर हर संभावित तरीकों से विचार करेगा। तीन दिवसीय बंगाल दौरे पर आये वित्त आयोग के प्रतिनिधिदल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान राज्य के वित्त विभाग की प्रस्तुतियों का गहनता से अवलोकन किया गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की आर्थिक अवस्था विगत कुछ सालों में काफी बेहतर हुई है जिसका मूल कारण जीडीपी विकास, ऋण प्रबंधन तथा कर राजस्व में वृद्धि है। सिंह ने कहा कि राज्य में रोजगार से लेकर शिक्षा व स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर काम हुआ है जो दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वित्त आयोग के साथ राज्य सरकार की बैठक काफी सार्थक रही। हमने विस्तृत रूप से राज्य की जरूरतों पर बातचीत की है और इस बैठक के बाद वित्त आयोग से काफी उम्मीदे हैं। उन्होंने आशा जतायी कि आयोग ऋण को लेकर राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार कहा है कि केंद्र सरकार राजस्व का बड़ा हिस्सा पूर्ववर्ती वाममोर्चा सरकार की ओर से लिये गये ऋण के किस्त और ब्याज के भुगतान बाबत काट लेती है जिसके कारण राज्य के विकास के लिए ज्यादा राशि नहीं बचती। राज्य सरकार ऋण के पुनर्गठन की माँग करती रही है।

उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग की टीम बुधवार को राज्य के कुछ मॉडल गाँवों की प्रगति व विकास कार्यों का जायजा लेगी। इस क्रम में टीम के सदस्य न्यूटाउन, आईटी पार्क, उत्तर 24 परगना जिले की मध्यमग्राम नगरपालिका और खेमिया ग्राम पंचायत इलाके में जायेंगे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में सामाजिक क्षेत्र में कई योजनाएँ शुरू की गयी हैं और नदिया जिला देश का खुले में शौच से मुक्त जिला बना है। इसके अलावा मातृ व शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है। बंगाल में जन्म दर 1.6 फीसदी है, जो भारत में निम्नतर है। इसके अलावा इसके सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। बंगाल के समक्ष बहुत ज्यादा कर्ज के साथ ही उच्च ऋण भुगतान की बाध्यता भी है। ●

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Samagya (समाज्ञा)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

राज्य की वित्तीय जरूरतों पर हुई चर्चा

एनके सिंह और ममता बनर्जी के साथ हुई लंबी बैठक

कोलकाता, समाज्ञा

मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने अपने सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संग बैठक की। बैठक राज्य सचिवालय नवान्न में दोनों के बीच लंबी समय तक चली। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक के बाद अपराह्न तीन बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनके सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान ममता ने एनके सिंह का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके बीच सकारात्मक बातचीत हुई। इस दौरान राज्य की वित्तीय जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई है एवं एनके सिंह ने भरोसा दिलाया है कि इससे संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय वित्त विभाग के पास जमा करेंगे। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा व संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एनके सिंह ने कहा कि आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल की जरूरतों को समझने हेतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विस्तार से चर्चा हुई है। राज्य की ग्रामीण इकाइयों से भी सीधे संवाद किया गया है एवं पश्चिम बंगाल में कृषि, उद्योग व आम लोगों की जरूरतों को समझा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य की जरूरतों के लिए राज्य में सभी दलों के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा पहले ही हो गई थी। मुख्यमंत्री ने भी जरूरतों की एक रिपोर्ट सौंपी है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। केंद्र की प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं में बंगाल का विशेष ध्यान रखने की अपील सीएम ममता बनर्जी ने की है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि अच्छे काम करने के बाद भी राज्य को केंद्र की पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ममता बनर्जी ने उन्हें बताया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो राज्य सरकार पर दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। पिछले सात सालों के कार्यकाल में उसे 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण चुकाना पड़ा है। सिर्फ चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 46 हजार करोड़ का बकाया चुकाना है।

मुख्यमंत्री की तरफ से वित्त आयोग को राज्य के राजस्व में हुई वृद्धि के बारे में भी बताया गया। ज्ञातव्य है कि एनके सिंह के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग का यह प्रतिनिधिमंडल अपने तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को कोलकाता पहुंचा था। बुधवार को यह दल दिल्ली लौट जाएगा।

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Dainik Vishwamitra (दैनिक विश्वमित्र)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले वित्त आयोग के अध्यक्ष

बैठक को सीएम ने बताया सकारात्मक

बंगाल की जरूरतों पर हुई विस्तार से चर्चा

कोलकाता, 17 जुलाई (निप्र)। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आज राज्य सचिवालय नवान्न में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने भेंट की। इस दौरान आयोग के सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के लोग भी राज्य सचिवालय नवान्न में मौजूद थे। राज्य सचिवालय नवान्न में ममता बनर्जी व एनके सिंह के बीच लंबी बैठक हुई। तकरीबन तीन घंटे तक चली इस बैठक को सकरात्मक बताया जा रहा है। बैठक के बाद अपराह्न तीन बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनके सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान ममता ने एनके सिंह का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके बीच सकारात्मक बातचीत हुई। इस दौरान राज्य की वित्तीय जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई है एवं एनके सिंह ने भरोसा दिलाया है कि इससे संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय वित्त विभाग के पास जमा करेंगे। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा व संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एनके सिंह ने कहा कि आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बंगाल की जरूरतों को समझने हेतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विस्तार से चर्चा हुई है। राज्य की ग्रामीण इकाइयों से भी सीधे संवाद किया गया है एवं पश्चिम बंगाल में कृषि, उद्योग व आम लोगों की जरूरतों को समझा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य की जरूरतों के लिए राज्य में सभी दलों के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा पहले ही हो गई थी। मुख्यमंत्री ने भी जरूरतों की एक रिपोर्ट सौंपी है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। केंद्र की प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं में बंगाल का विशेष ध्यान रखने की अपील सीएम ममता बनर्जी ने की है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि अच्छे काम करने के बाद भी राज्य को केंद्र की पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ममता बनर्जी ने उन्हें बताया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो राज्य सरकार पर दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। पिछले सात सालों के कार्यकाल में उसे 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण चुकाना पड़ा है। सिर्फ चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 46 हजार करोड़ का बकाया चुकाना है। मुख्यमंत्री की तरफ से वित्त आयोग को राज्य के राजस्व में हुई वृद्धि के बारे में भी बताया गया। आज 15वें वित्त आयोग की टीम दिल्ली रवाना होगी।

नवान्न में 15वें वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा वित्त आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह। विश्वमित्र

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Chhapte-chhapte (छपते-छपते)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

ममता नबान्न में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह के साथ संवाददाता सम्मेलन में।

राज्य सरकार के नये प्रयास प.बंगाल में अच्छा रोजगार सृजन करेंगे : वित्त आयोग

■ विशेष संवाददाता

कोलकाता, 17 जुलाई ऊर्जा क्षेत्र, शहरीकरण और अपनी तुलनात्मक विशेषताओं के क्षेत्र में नये प्रयास करके पश्चिम बंगाल सरकार रोजगार-सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सकती है। यह उपलब्धि पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार का कारक बनेगी। 15वें वित्त आयोग के अधयक्ष श्री एन. के. सिंह ने आज राज्य सचिवालय में मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए यह मंतव्य किया। श्री सिंह ने कहा कि वित्त आयोग का मानना है कि आधारभूत सूक्ष्म वित्तीय पैमानों के हिसाब से और जी डी पी वृद्धि दर में पश्चिम बंगाल ने विगत कुछ वर्षों में अच्छी सफलता प्राप्त की है।

श्री सिंह ने कहा कि वित्त प्रबंधन के युक्तिसंगत नये उपाय करके राज्य सरकार ने राजस्व उगाही में तथा कराधान संग्रह में वृद्धि की सफलता प्राप्त की है। राज्य सरकार ने आयोग का ध्यान विरासत में मिले ऋण के भारी ब्याज के भुगतान की ओर खींचा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मुद्दे के समाधान हेतु 15 वाँ वित्त आयोग ऐसे उपाय करेगा कि यह आर्थिक बोझ राज्य की वित्तीय प्रगति में लगातार रोड़ा नहीं बना रहे। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न पदाधिकारियों और प्रतिनिधिमंडलों से हुई सकारात्मक बातचीत के आधार पर आयोग राज्य- प्रशासन के साथ बंगाल के लिए अल्पावधि व दीर्घावधि सुधारों के प्रति तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने काफी पहले ही एक स्मरण पत्र आयोग को दिया है जो काफी सराहनीय है। समय पर मिले इस स्मरण पत्र में फंडिंग को लेकर कई समस्याओं का जिक्र है जिन पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि कल नगरपालिका और नगर निगमों के प्रतिनिधियों के साथ वित्त आयोग की बैठक हुई थी। इसमें केन्द्र प्रायोजक परियोजनाओं का फंड बढ़ाने की मांग की गयी थी। इस अवसर पर श्री सिंह के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वित्तमंत्री श्री अमित मित्रा तथा वित्त आयोग के सदस्यगण भी उपस्थित थे।

PRESS INFORMATION BUREAU

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Bharat Mitra (भारत मित्र)
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/07/2018

मुख्यमंत्री से मिले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष

बैठक काफी सफल रही : ममता

कोलकाता, 17 जुलाई (नि.स.)। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह मंगलवार को अपने सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। राज्य सचिवालय नवान्न में दोनों के बीच लंबी बैठक हुई। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक के बाद अपराह्न तीन बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनके सिंह ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान ममता ने एनके सिंह का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके बीच सकारात्मक बातचीत हुई। इस दौरान राज्य की वित्तीय जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई है एवं एनके सिंह ने भरोसा दिलाया है कि इससे संबंधित रिपोर्ट केंद्रीय वित्त विभाग के पास जमा करेंगे। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा व संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एनके सिंह ने कहा कि आगामी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल की जरूरतों को समझने हेतु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विस्तार से चर्चा हुई है। राज्य की ग्रामीण इकाइयों से भी सीधे संवाद किया गया है एवं पश्चिम बंगाल में कृषि, उद्योग व आम लोगों की जरूरतों को समझा गया है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की जरूरतों के लिए राज्य में सभी दलों के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा पहले ही हो गई थी। मुख्यमंत्री ने भी जरूरतों की एक रिपोर्ट सौंपी है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। केंद्र की प्रस्तावित पंचवर्षीय योजनाओं में बंगाल का विशेष ध्यान रखने की अपील सीएम ममता बनर्जी ने की है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि अच्छे काम करने के बाद भी राज्य को केंद्र की पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ममता बनर्जी ने उन्हें बताया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो राज्य सरकार पर दो लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। पिछले सात सालों के कार्यकाल में उसे 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण चुकाना पड़ा है। सिर्फ चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 46 हजार करोड़ का बकाया चुकाना है। मुख्यमंत्री की तरफ से वित्त आयोग को राज्य के राजस्व में हुई वृद्धि के बारे में भी बताया गया। ज्ञातव्य है कि एनके सिंह के नेतृत्व में 15वें वित्त आयोग का यह प्रतिनिधिमंडल अपने तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार को कोलकाता पहुंचा था। बुधवार को यह दल दिल्ली लौट जाएगा।

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper	:-	Jansatta (जनसत्ता)
Language	:-	**ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU**
Place of Publication	:-	**Kolkata (West Bengal)**
Date of Publication	:-	19/07/2018

राज्य सचिवालय नवान्न में मंगलवार को 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करतीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।

NDTV

West Bengal Suggests Alternative Devolution Formula To Finance Commission Read In

The panel chief also said the commission "will explore all possible ways" to restructure West Bengal's debt as demanded by the state.

All India | Indo-Asian News Service | Updated: July 19, 2018 00:25 IST

PROMOTED

The panel, headed by Chairman NK Singh has been on a three-day visit to the state.

UNI
United News of India
India's Multi Lingual News Agency
Thursday, Jul 26 2018 | Time 14:15 Hrs(IST)

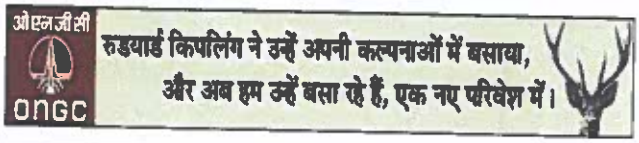

States

Posted at: Jul 18 2018 10:46PM

Share

15th Finance Commission team visits IT Sector, Eco Park & Madhyamgram Municipality

Madhyamgram, Jul 18 (UNI) Chairman of 15th Finance Commission N.K.Singh along with other members of the Commission today visited IT Sector of New Town and Eco Park at Rajarhat area.

Finance Commission members then visited Khemia Khamarpara Gram Panchayat at Barasat sub division of North 24 Pargana district of West Bengal. They have discussed about the financial and developmental activities of the Khemia Khamarpara Gram Panchayet with members of the Panchayet.

This team also visited Madhayaymgram Municipality of North 24 Parganas. District Magistrate and other officials welcomed Mr Singh and other members of the Commission. A meeting was held among them. Finance Commision members observed how a Gram Panchayet of West Bengal run their normal activites.

The Commission led by Chairman Mr Singh made a courtesy call on Chief Minister Mamata Banerjee yesterday. Presentations by the State government officials were also presented before the Commission. After detailed meeting with West Bengal government yesterday, Mr Singh, in a press conference saidthe Commission has taken a note of the detailed presentation made by the state government.

Commission appreciated the new initiatives taken by the state government in the fields of Power Sector, creation of leather hub, a financial hub, more orderly pace of urbanization, utilizing comparative factor advantages which are creating huge employment opportunities.

The Commission also noted that West Bengal economy is strategically placed bordering Nepal, Bangladesh and Bhutan and is a driver economy for many other economies in the vicinity.

Notwithstanding the current growth momentum and the new initiatives taken, Mr Singh highlighted the need to consider and examine the legacy issues particularly the huge debt overhang and the need for structural measures in a manner which does not become a permanent drag on the state economy.

Commission during the detailed deliberation brought out some concerns like low capital expenditure as a percentage of total expenditure. It was assured by the state government that there has been a substantial enhancement in capital expenditure.

UNI BM

UNI Photo

NEW DELHI, JULY 26 (UNI):- Defence Minister Nirmala Sitharaman, Chief of the Army Staff General Bipin Rawat, Chief of the Naval Staff Admiral Sunil Lanba and Chief of

Other Links

UNIVARTA (News Agency)
Indian News Agency

UNI-Urdu Service(News Agency)
Indian News Agency

Newswrap

Newswrap1

More News

Nathpa Jakhari & Rampur Hydro project resume power generation

26 Jul 2018 | 1:53 PM

Shimla, Jul 26 (UNI) Asia's biggest 1500 Nathpa Jakhari and 412 MW Rampur hydro power station on Thursday resumed its generation after remaining break down for past 12 hrs due to shooting up of silt level in the Sutlej river beyond project threshold.

he Statesman
Thursday, 26 July, 2018

15th Finance board chairman lauds WB govt

WB govt has made enormous progress on macroeconomic parameters, debt management, GDP growth and own tax revenues: N K Singh.

(http://twitter.com/sh... text=15th Finance board chairman lauds
(mailto:test... subject=15th Finance board chairman lauds
(https://www.f... u=https... finance- board- chairman- lauds- wb- govt- 150266...

Statesman News Service | Kolkata | July 18, 2018 4:31 am

/est Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. (Photo: IANS/File)

All parties sans BJP echo Mamata's demand to restructure debt before Finance Commission

Team MP (/) | 16 July 2018 11:27 PM

Like 0 Share Tweet

S://(HTTP[illegible]LINK? URL=H[illegible]ATAS- [illegible]TH- SHARE%26UTM_PARTNER%3DMPOST%26UTM[illegible]=ALL [illegible]ION) [illegible]ON)

olkata: Echoing Mamata Banerjee, all political parties except BJP demanded debt restructuring [illegible] Finance Commission.

e Fifteenth Finance Commission, headed by chairman N K Singh, held a meeting at Nabanna Sabhaghar on Monday. [illegible] presentatives of all the political parties, heads of the civic bodies in the state and Zilla Parishads were present in the meeting.

ficials of the state Finance department were also present in the meeting. Amit Mitra, the state Finance minister, felicitated e chairman.

UNI
United News of India
India's Multi Lingual News Agency
Thursday, Jul 26 2018 | Time 14:16 Hrs(IST)

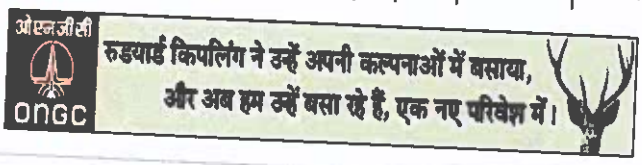

Posted at: Jul 16 2018 9:14PM

Democracy truly cannot succeed unless those expressing their choice prepared to choose wisely: Singh

Kolkata, Jul 16 (UNI) Chairman of the 15th Finance Commission N K Singh on Monday said democracy truly cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose widely.

" Are the governments entitled to circumscribe the option of successor governments? "

asked the Chairman of the 15th Finance Commission here while deliberating on an interactive session on 'Democracy and Development, organised by the Indian Chamber of Commerce (ICC).

He said democracy and development are two best choices people hanker after.

Popularly elected Governments undertake decisions resulting in fiscal profligacy, excessive market borrowing leaving behind an excessive pile of debt to successor Governments would suffer under the impact of the decisions taken earlier. There cannot be a judicial recourse to this; any ruler bias would suffer from moral hazards, Mr Singh said.

He said on the one hand, interfering and compromising with the mandate of the Government in office and its elected representatives, on the other hand, what happens to the lingering impact of the past decisions on the flexibility and freedom of choice of incumbent governments.

Mr Singh even advised the social media companies to adjust their sites to make clearer if a post comes from a friend or a trusted source. They could accompany the sharing of

UNI Photo

NEW DELHI, JULY 26 (UNI):-People using umbrella during rain in Parliament House, New Delhi on Thursday. UNI PHOTO-JA14U

Other Links

UNIVARTA (News Agency)
Indian News Agency

UNI-Urdu Service(News Agency)
Indian News Agency

Newswrap

Newswrap1

Finance Commission may incentivise states doing well in population management: Chairman

BY PTI | JUL 16, 2018, 09.00 PM IST

Post a Comment

KOLKATA: The 15th Finance Commission (FC) may consider incentixising those states who are doing well in population management as the terms of reference did allow for that, its chairman N K Singh said today.

In the 14th FC, both the population data of 1972 and 2011 were used, he said.

Big Change:
The end of Five-Year Plans: All you need to know

Many states, mostly those in the south, where population levels have declined, had opposed choosing 2011 as the base year for population census and not 1972 in the terms of reference of the 15th FC.

"The states have correctly placed their demands to the President saying that they will lose if 2011 is taken as the year for taking population data," Singh said at an Indian Chamber of Commerce (ICC) event here.

He said that the FC would have to abide by the terms of reference given, adding "which also allows for incentivising states for doing better population control," he said.

"There will be no bias or prejudice governing us rather than what the Constitution does," he said.

In the 14th FC, both the population data of 1972 and 2011 were used, he said.

Earlier in the day, Singh met representatives of political parties of West Bengal and held discussions with them.

Singh said all the parties had raised the issue of the state's debt during the deliberations.

Singh is scheduled to meet Chief Minister Mamata Banerjee tomorrow.

The 15th FC, formed in November 2017, would have to submit its report to the Centre by end 2019.

Stay on top of business news with The Economic Times App. Download it Now!

Powered by

Live Market | Industry | About Us
News | Newsletters | Create Your Own Ad
Portfolio | Commodities | Advertise with Us
Mobile | Speed | Terms of Use & Grievance Redressal
Live TV | Blogs | Privacy policy
Biz Listings | RSS

FOLLOW US

Download it from APP STORE | Download it from GOOGLE PLAY | Download it from Windows Store

Finance Commission may consider sops for States with better population control

OUR BUREAU

Renewed offer NK Singh, Chairman,15 th Finance Commission, speaking at an interactive session organised by the Indian Chamber of Commerce on Monday

KOLKATA, JULY 16

NK Singh, Chairman of the 15th Finance Commission, on Monday said the panel may consider providing incentives to States that have managed to achieve the objective of population control while distributing resources between Centre and States.

If considered, this could well be a departure from the earlier practice, which used data from the 1971 Census. The 15th Finance Commission's terms of reference stipulate that data should be used from the 2011 census. This has been objected by some States, which have achieved progress in controlling population over the years.

"We have to abide by the terms of reference given by the President...We may consider incentivising those States that have achieved good progress in demographic management," Singh said at an interactive session organised by the Indian Chamber of Commerce here.

THE NEW INDIAN EXPRESS
Thursday, July, 26, 2018 02:24:49 PM

Finance Commission to address West Bengal's debt restructuring demand

The commission has taken a serious note of the expectation of the state government and will explore possible ways within our mandate."

Published: 18th July 2018 12:33 AM | Last Updated: 18th July 2018 12:33 AM

A+ A A-

Bloomberg | Quint

Taken Note Of West Bengal's Debt Overhang, Says 15th Finance Commission

PTI
@PTI_News

Updated on:17 July 2018, 11:06 PM
Published on:17 July 2018, 11:06 PM

The 15th Finance Commission today said it has taken "serious note" of the West Bengal government's debt overhang and would explore options within its mandate so that it does not remain a "permanent drag" on the state's economy.

After holding a meeting with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Finance Minister Amit Mitra and other officials, the Commission's Chairman NK Singh lauded the state government's performance during the past few years.

> West Bengal's total debt stood at Rs 3.40 lakh crore, which is one of the highest among states.

"The Commission recognises that in the last few years, West Bengal's economy has made enormous progress on GDP growth, debt management and increasing its own tax revenue," Singh told reporters after the meeting. He added that the state government has submitted a detailed memorandum well in advance which enabled the Commission to understand specific demands.

Chief Minister Mamata Banerjee has been seeking loan waiver and generous central funds for West Bengal and had met Prime Minister Narendra Modi in this regard last year.

Singh further said that the chief minister placed a detailed set of comments, followed by observations along with presentations.

The state government has brought forward the need for the Finance Commission to look at the legacy issue of debt overhang and the innovative ways that this large debt overhang could be redressed in a manner that it does not become a permanent drag on the economy of the state, Singh said.

As per the Terms of Reference which has been determined by President Ram Nath Kovind, the Finance Commission would ensure that performance is not penalised in any way and efficiency and equity rewarded.

Also Read: Six States Oppose Terms Of Reference Of 15th Finance Commission

If interest payment of past debts forecloses the government's revenue then, of course, that is a drag on which they would like to see a structural solution to what can be done, he said.

The state has made significant strides in many indices of human development, particularly in the fields of education and health which will have multiplier effect on the long-term growth of West Bengal's economy, he said.

Describing the meeting as a "good one", the chief minister said the state government is expecting the Commission to consider debt restructuring proposal.

2018 Bloomberg L.P. All Rights Reserved

livemint

Finance Commission to consider West Bengal's request for restructuring debt

15th Finance Commission chairman N.K. Singh says as the interest payment on piled up debts is squeezing resources available for development, West Bengal wants a 'structural solution'

Last Published: Tue, Jul 17 2018. 09 31 PM IST

Arkamoy Dutta Majumdar

Enter email for newsletter Sign Up

est Bengal CM Mamata Banerjee told the panel on Tuesday that her government had in 2011 inherited outstanding debt of around ₹200,000 crore from the Left Front's 34-year unbroken rule. File photo: Mint

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- The Telegraph
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/7/18

Finance panel seeks 'clean' Bengal data

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta: The 15th Finance Commission has asked the Bengal government to take up a joint exercise with the Central Statistics Office (CSO) to reconcile "some of its macroeconomic data" and submit the revised figures by August.

"The finance minister (Amit Mitra) will reconcile some of the macroeconomic indicators with the CSO and submit it to us by August," N.K. Singh, the chairman of the commission, said on Tuesday after talks with chief minister Mamata Banerjee and Mitra.

The commission members are on a two-day visit to Bengal for meetings with political parties and the government as part of a nation-wide exercise before handing in their recommendations to the Centre on a funds devolution formula. The commission advises the Centre how it should share taxes with the states for five years. In case of the 15 Finance Commission, the period will start from April 1, 2020.

The decision to seek "reconciled" data is significant because the state of the Bengal economy in recent years has become a matter of mystery among economists and researchers, who have complained about the lack of "reliable" numbers on basic indicators.

NK Singh (extreme right) **with chief minister Mamata Banerjee and finance minister Amit Mitra** (centre) **at Nabanna in Calcutta on Tuesday.** Telegraph picture

The Economic Survey tabled by the Union finance ministry in January 2018 mentions the NSDP (net state domestic product) for all states, except Bengal's. "The estimates of West Bengal for new series with base year 2011-12... are under examination," the survey noted.

Sources in Nabanna said the finance commission members made it clear that until the state's macroeconomic data are approved by the CSO, the panel will not be able to work on Bengal's demands, which include higher devolution of central taxes and debt restructuring.

The commission members, however, praised the Mamata government on its performance.

"Bengal has worked on enhancing its revenue generation, implementing e-payments and debt management. It has enhanced capital expenditure, which was a cause of concern earlier. Its special stress on health and education will help growth," said Singh, the chairman.

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- The Asian Age
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18/7/18

Finance Commission chairman N.K. Singh talks with chief minister Mamata Banerjee as state finance minister Amit Mitra looks on during the press conference on 15th Finance Commission at Nabanna Savaghar in Kolkata on Tuesday.
— ABHIJIT MUKHERJEE

'Taken serious note of Bengal debt overhang'

Kolkata, July 17: The 15th Finance Commission on Tuesday said it has taken a "serious note" of the West Bengal goverment's debt overhang issue and would explore options within its mandate so that it does not remain a "permanent drag" on the state's economy.

After holding a meeting with West Bengal chief minister Mamata Banerjee, finance minister Amit Mitra and other officials, the commission's chairman N.K. Singh lauded the state government's performance during the past few years.

West Bengal's total debt stood at ₹3.40 lakh crore, which is one of the highest among states.

West Bengal's total debt stood at ₹3.40 lakh crore, which is one of the highest among states

"The commission recognises that in the last few years, West Bengal's economy has made enormous progress on Gross Domestic Product (GDP) growth, debt management and increasing its own tax revenue," Singh told reporters after the meeting. He said the state government has submitted a detailed memorandum well in advance which enabled the Commission to understand specific demands. Ms Banerjee has been seeking loan waiver and generous Central funds for West Bengal and had met Prime Minister Narendra Modi in this regard last year.

Mr Singh further said that the chief minister placed a detailed set of comments, followed by observations along with presentations.

The state government has brought forward the need for the Finance Commission to look at the legacy issue of debt overhang and the innovative ways that this large debt overhang could be redressed in a manner that it does not become a permanent drag on the economy of the state, Mr Singh said. — PTI

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

9

Name of Newspaper :- Dainik Statesmen
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18

ঋণকাঠামো সংস্কারে রাজ্যের দাবিতে সহমত অর্থ কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি – ঋণ পরিশোধের কাঠামোগত সংস্কার, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাড়ানো নিয়ে রাজ্যের দাবির সঙ্গে সহমত হল পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। মঙ্গলবার অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিংহ রাজ্যের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক পরিচালন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তাঁর মতে, এই রাজ্যের সঙ্গে তিনটি প্রতিবেশি দেশ (বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান) এবং দুটি রাজ্যের (সিকিম, ঝাড়খণ্ড) সীমান্ত যুক্ত। তাই এই রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। তাই পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক উন্নয়নের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে বলেই মনে করছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। এই কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তাই এই রাজ্যের দাবি প্রতি কমিশনের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে আশার আলো দেখছে সরকার।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সঙ্গে বৈঠক খুবই ভালো হয়েছে। বিশেষ করে ঋণ পরিশোধের কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। মমতা বলেন, রাজ্যের আবেদনগুলি গ্রাহ্য হবে বলেই আশা রাখি। এদিন জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অনুদান পাওয়ার নীতির সংশোধন এবং ঋণ কাঠামোর সংস্কার নিয়ে রাজ্যের আবেদনে সদর্থক ভূমিকা নেবে কমিশন। রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টি, রাজস্ব বৃদ্ধি, ঘাটতি কমানো, জিএসটি বৃদ্ধি, রাজ্যের সামাজিক প্রকল্পগুলির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয় কমিশনের কাছে। সেখানে বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের কাটছাঁট, রাজ্যের কাছ থেকে নেওয়া কর বণ্টনের ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে বঞ্চনা, নদী সংস্কারে কেন্দ্রের উদাসীনতা ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রের প্রতি সরাসরি অভিযোগও আনা হয়েছে।

বৈঠকের পর অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিংহ বলেন, রাজ্যের তরফে দেওয়া স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। গত কয়েক বছরে রাজ্যের অর্থনৈতিক সূচকগুলি যেমন জিডিপি বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায়, গঠনমূলক মূলধনী ব্যয় খুবই আশাব্যঞ্জক। প্রত্যক্ষ করকাঠামো এবং ই-গভর্নেন্স -এর জন্য এই সাফল্য বলে মন্তব্য করেন এন কে সিংহ। এছাড়া রাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের নমনীয় আর্থিক নীতিরও প্রশংসা করেন তিনি। রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, মেধাভিত্তিক মানবসম্পদের বিকাশ, তথ্য প্রযুক্তি এবং চর্মশিল্পে শ্রমনিবিড় কর্মোদ্যোগ, সুষ্ঠু ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও রাজ্যকে বাহবা দেয় কমিশন।

অর্থমন্ত্রী এদিন রাজ্যের তরফে দেওয়া স্মারকলিপিতে টার্মস অফ রেফারেন্স নিয়ে কেন্দ্রের নীতির সরাসরি সমালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়ার নীতি নির্ধারণ করেছে মোদি সরকার। যার ফলে বিহার, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি গো বলয়ের রাজ্যগুলি যেখানে জনসংখ্যা বেশি, তারা উপকৃত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা কর্মসূচিকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ রাজ্যের ক্ষেত্রে লোকসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন নীতির ফলে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দ কমছে রাজ্যের। এই বিষয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বেশ কয়েকবার সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অথরিটি (সিএসও) -এর কাছে তেরটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। ১৯৭১ সালের জনগণনা ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নির্ধারণ করার আবেদন নিয়ে ফের আগস্ট মাসে সিএসও'র কাছে দরবার করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। সোমবার প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত একই যুক্তি রেখেছিলেন অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের কাছে।

অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা জানান, বিষয়টি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষ বলে এতে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই। তবে ঋণভার লাঘবের জন্য বিশেষ প্যাকেজের দাবি খতিয়ে সহানুভূতিশীল পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। এই বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান। সেই রিপোর্ট আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এই বৈঠক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কেন্দ্র ও রাজ্যের যথাযথ আর্থিক সম্পর্কের নিরিখে।

অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক সেরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন বিশিষ্ট শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার প্রয়াত মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। উল্লেখ্য সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মা ও বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রয়াত রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কার স্ত্রী সুশীলা গোয়েঙ্কা প্রয়াত হন সোমবার সন্ধ্যায়।

Finance Commission supports reforms in loan structure in unison with State demand.
(Dainik Statesman, Bengali, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Ananda Bazar Patrika
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18

■ **এক মঞ্চে:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিংহ। *ছবি: দীপঙ্কর মজুমদার*

ঋণ: আশ্বাস দিল কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঋণ পুনর্গঠন নিয়ে রাজ্যের দীর্ঘদিনের দাবি গুরুত্বসহকারে বিবেচনার আশ্বাস দিল পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ঋণের বোঝায় রাজ্য নাস্তানাবুদ হলেও গত সাত বছরে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফলে ঋণ শোধ করতে গিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।" রাজ্যের আর্থিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করার দাবি জানান তিনি।

এ দিন বাম আমলে নেওয়া ঋণের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী কমিশনকে জানান, গত সাত বছরে সুদ ও আসল শুধতেই ২ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। চলতি বছরেও এই খাতে ৪৬ হাজার কোটি টাকা চলে যাবে। তিনি বলেন, "আশা করব, কমিশন রাজ্যের ঋণ পুনর্গঠন করতে পদক্ষেপ করবে।"

পরে মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিংহ সাংবাদিকদের বলেন, "রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ঋণভার। কমিশন তা লাঘব করার দাবি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে।" তিনি জানান, আগের জমানার ঋণের বোঝা যে ভাবে এই সরকারকে বহন করতে হচ্ছে তা সত্যিই কঠিন কাজ। এক দিকে ঋণের ফাঁদ থেকে রাজ্যকে মুক্ত করা, অন্য দিকে সুদ মেটানোর প্রক্রিয়া লাঘব করতে কাঠামোগত সমাধান বার করা আবশ্যক। তাঁর কথায়, "রাজ্যের তরফে ঋণমুক্তির জন্য জোরালো যুক্তি ও পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। কমিশন তার এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে ঋণভার কমানোর প্রস্তাব খতিয়ে দেখছে।"

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ঋণের বোঝা সামলেও বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে রাজ্য। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, নতুন পরিকাঠামো তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি নেওয়া ১৮ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "শুধু পরিকাঠামো নয় রাজ্যের ৯০% মানুষের কাছে সরকারের কোনও না কোনও সুবিধা পৌঁছেছে।"

মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি মেনে নিয়ে এন কে সিংহ বলেন, "স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে রাজ্যের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘমেয়াদে এই দুই ক্ষেত্রে বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। বিদ্যুৎ পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং নগরায়ণের ক্ষেত্রেও রাজ্যের কাজ প্রশংসার যোগ্য।" মূলধনী ব্যয় বাড়ানো, সরাসরি সুবিধা বিলির প্রকল্প এবং ই-পেমেন্টের ব্যাপারে রাজ্যের প্রশংসা করেন তিনি। রাজ্য যে ভাবে নিজস্ব আয় বাড়িয়েছে, বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে, তাতে সন্তোষপ্রকাশ করেছে কমিশন।

ভিতরে

■ **আরও খবর** পৃঃ ৬

Loan: Commission gives assurance. (Anandabazar Patrika, Bengali, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Ananda Bazar Patrika
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18

অর্থ কমিশনে বামেদের প্রশ্ন

অর্থ কমিশনের কাজ শুধু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে নয়। স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলি যথাযথ আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে কি না, তা-ও তাদের দেখা উচিত বলে আর্জি জানিয়েছে বামেরা। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত ও শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। পরে অশোকবাবু বলেন, "অন্য সব জেলায় পরিকল্পনা কমিটি আছে। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি যে হেতু বামেদের এবং তাঁকে কমিটিতে রাখতে হবে, তাই কমিটিটাই তৈরি হয়নি। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের অন্যায় নিয়ে প্রশ্ন তুলছে কিন্তু নিজেরাই সংবিধানের সংস্থান লঙ্ঘন করছে।"

Leftists' question in Finance Commission. (Anandabazar Patrika, Bengali, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Ananda Bazar Patrika.
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18.

রাজ্যের সঙ্গে কথা বলেই কেন্দ্রীয় প্রকল্প, চান মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা

অর্থ কমিশনের মঞ্চেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কমিশনকে জানান, চতুর্দশ অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয় কর থেকে রাজ্যের প্রাপ্য ৩২% থেকে বাড়িয়ে ৪২% করেছিল। কিন্তু তা আসলে লোক দেখানো। কারণ, কেন্দ্র একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে বহু প্রকল্প পুনর্গঠন করে। ৩৮টি কেন্দ্রীয় প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। ফলে ওই প্রকল্পগুলির বকেয়া কাজের টাকার দায় এসে পড়ে রাজ্যের ঘাড়ে। ৫৮টি প্রকল্পে রাজ্যের খরচের ভাগ বাড়িয়ে দেয় কেন্দ্র।

মুখ্যমন্ত্রী কমিশনকে বলেন, "আমরা বারবার বলেছি, রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করা হোক। কারণ, নতুন প্রকল্প এলেই তার আর্থিক ভার রাজ্যের ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু সে সব কিছুই শোনা হয়নি।" পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্যের আর্জি, ভবিষ্যতে কেন্দ্র যাতে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও প্রকল্প ঘোষণা করতে না-পারে, সে ব্যাপারে তারা সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করুক। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় করের ন্যায্য পাওনা থেকেও রাজ্যকে বারবার বঞ্চিত করা হয়েছে বলে কমিশনের কাছে অভিযোগ মমতার। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সেস-সারচার্জের ভাগও রাজ্যগুলিকে দেওয়া হোক। বর্তমানে সেস-সারচার্জের ভাগ রাজ্যগুলি পায় না। তাই কেন্দ্র অনেক সময়ই কর কমিয়ে সেস বা সারচার্জ বসিয়ে দেয়। সাম্প্রতিক অতীতে পেট্রল-ডিজেলের উপরে প্রায় ৮ টাকা কেন্দ্রীয় কর কমিয়ে সমপরিমাণ টাকা সেস হিসেবে ধার্য করেছে।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার আরও কয়েকটি উদাহরণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কমিশনকে জানান, ইউপিএ সরকার পিছিয়ে পড়া এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্যের জন্য ৮৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। মোদী সরকার এই খাতে ২৬৫০ কোটি টাকা দেয়নি। তা ছাড়া, চতুর্দশ অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পুরোটাই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচের সুপারিশ করায় জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক কাঠামো দুর্বল হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের দাবি

- কেন্দ্রীয় করের প্রাপ্য ৪২ থেকে ৫০% করা
- কেন্দ্রীয় সেস ও সারচার্জেরও অংশ
- পাঁচ বছরে ৯০,১৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি অনুদান
- পরিমাঠামো ক্ষেত্রে ১, ৪৬, ৬৯৩ কোটির অনুদান
- পুরসভা ও পঞ্চায়েতের জন্য ৬৪,৩১৯ কোটি টাকা
- প্রশাসনিক সংস্কার ও অভিনব ভাবনার প্রকল্পে ২৫,৮৩০ কোটি

Mamata wants Central schemes after discussion with State. (Ananda Bazar Patrika, Bengali, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

(5)

Name of Newspaper :- Ei Samay.
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18

দিদির রাজ্যে উন্নয়ন নজর কাড়ল অর্থ কমিশনের

এই সময়: পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে উন্নয়নের জোয়ার মন ছুঁয়ে গেল পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কর্তাদের। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক তথা মানব সম্পদ বিকাশের নানা ক্ষেত্রে রাজ্যের যে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে, তা জানাতে কোনও দ্বিধা করেননি খোদ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিংহ।

এর পাশপাশি, ঋণের 'উত্তরাধিকার' লাঘবে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করার আশ্বাস দিয়েছে কমিশন। এই ঋণের বোঝা যে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক বিকাশের পথে অন্তরায় তার সঙ্গেও একমত চেয়ারম্যান। তবে ঋণ মকুবের ব্যাপারে তিনি কোনও নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেননি। শুধু জানিয়েছেন যে, এই ব্যাপারে কমিশন তার মতামত রাষ্ট্রপতিকে জানাবে।

মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী এবং এন কে সিংহ একযোগে সাংবাদিক বৈঠক করেন। শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী কমিশন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা ব্যক্ত করেন। তাঁর কথায়,, 'কমিশনের সঙ্গে খুবই ভালো আলোচনা হয়েছে। চেয়ারম্যান-সহ কমিশনের সদস্যরা আমাদের সঙ্গে যথেষ্টই সহযোগিতা করেছেন। বস্তুত, কমিশনের কাছে আমাদের অনেক আশা। আমরা আশাবাদী, রাজ্যের বিপুল ঋণের বোঝার পুনর্গঠনের ব্যাপারটি কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েই বিচার করবে। পাশাপাশি, কৃষি, শিল্প-সহ নানা বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। আরও আলোচনা চলছে।'

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে মমতা — শুভজিৎ চন্দ্র

কমিশনের কাছে মুখ্যমন্ত্রী কতকগুলি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, কমিশনের তরফে ২০১১ সালের জনসংখ্যার হিসেব টার্মস অফ রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে না। বরং, ১৯৭১ সালের জনসংখ্যাই সূচক হিসাবে ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিগ্রাহ্য হত। পাশাপাশি, প্রায় দু'লাখ কোটি টাকার ঋণের বোঝার উত্তরাধিকার রাজ্যের অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে বলেও মমতা সরব হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, এই ব্যাপারে রাজ্যের সমস্যা লাঘবে কেন্দ্রের কোনও হেলদোল নেই। ঋণ কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে দিল্লির তরফে কোনও সহায়তা মিলছে না। কেন্দ্রীয় রাজস্বের অন্তত ৫০% রাজ্যকে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সিংহের মতে, 'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ঋণের বোঝার উত্তরাধিকারের বিষয়টি আমাদের কাছে জোরালো ভাবেই পেশ করেছেন। এই ঋণ ক্রমাগত সুদ সমেত মেটানোর প্রক্রিয়া চলতে থাকলে রাজ্যের উপর একটি চিরস্থায়ী চাপের সৃষ্টি হয়। এতে রাজ্যের আয়েও টান পড়ছে বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জানিয়েছে। এটা আমরা দেখছি। তবে টার্মস অফ রেফারেন্সের বিষয়টি কমিশন নির্ধারণ করে না। এটা ভারতের রাষ্ট্রপতির ঠিক করা।'

তবে সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের বিভিন্ন আর্থিক সূচকের উন্নয়ন যে মন কেড়েছে কমিশনের, তা এ দিন পরিষ্কার জানিয়েছেন সিংহ। যেমন কর আদায়, উৎপাদনের গড় হার, আর্থিক নিয়মকানুনের সরলীকরণ বা ঋণ প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে রাজ্য ভালই এগিয়েছে। তাঁর কথায়, 'স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো মানব সম্পদ উন্নয়নের সূচকগুলিতেও রাজ্যের অগ্রগতি লক্ষণীয়। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে আর্থসামাজিক বিকাশে বহুমুখী ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। শ্রমনির্ভর কর্মসংস্থান, দক্ষতার বিকাশ ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতিও রাজ্যের সাফল্যের তালিকায় রয়েছে।'

কমিশনের কর্তা রাজ্য সরকারের তরফে পেশ করা বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূচকের ক্ষেত্রে 'অসামঞ্জস্য' দূর করার উপরও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, অগস্টেই সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিকস অফিস বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত সূচকের পুনর্বিন্যাস করছে। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকারও তার সূচকগুলিতে কোনও অসামঞ্জস্য থাকলে, তা দূর করবে বলেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন।'

Finance Commission is taken over by development in 'Didi's State. (Ei Samay, Bengali, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Bartaman
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18.

অর্থ কমিশনের সামনে কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব হলেন মমতা

ঋণের চাপ কমাতে পদক্ষেপের আশ্বাস চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্য সফররত পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সামনে কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনা নিয়ে তথ্য তুলে ধরে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জঙ্গলমহল সহ যেসব জায়গায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারও উল্লেখ করেন তিনি। বিভিন্ন সভায় যেভাবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন, মঙ্গলবার সেই পরিচিত ভঙ্গিতেই অর্থ কমিশনের সদস্যদের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারকে এক হাত নিতে ছাড়েননি মমতা। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রের অনুদান কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে রাজ্যের কোষাগারের উপর চাপ পড়ছে। কেন্দ্র যেন এটা না করে, তার জন্য অর্থ কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেই সঙ্গে রাজ্যের উপর চেপে বসা বিপুল ঋণের বোঝা কমানোর জন্যও আর্জি জানানো হয়। কীভাবে তা কমানো যেতে পারে, তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিং। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। প্রসঙ্গত, গত ২০০৩-০৪ আর্থিক বছর থেকে বাম সরকারের নেওয়া ঋণের সুদ এবং আসল মেটাতে হচ্ছে মমতা সরকারকে। অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, ২০১৭ সাল থেকে এই সুদের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। চলতি আর্থিক বছরে মেটাতে হবে ৪৬ হাজার কোটি টাকা। সুদ বৃদ্ধির জেরে বেড়েই চলেছে রাজ্যের ঋণের বোঝা।

এদিন বেলা সাড়ে ১২টা থেকে অর্থ কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে ১২ পাতার একটি স্মারকলিপি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই স্মারকলিপিতে রাজ্যের সাফল্যের দিক তুলে ধরার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার দিকও তুলে ধরা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশাল ঋণের বোঝা নিয়ে সরকারের কাজ শুরু করি। সেই ঋণ থেকে মুক্তি পেতে ঋণ পরিশোধের পরিকাঠামো পরিবর্তন করার দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সদর্থক উত্তর পাইনি। পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য ইউপিএ সরকারের আমলে বিআরজিএফ থেকে বিশেষ প্যাকেজে ৮৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কেন্দ্রের নতুন সরকার সেই প্যাকেজের ২৬৫০ কোটি টাকা আটকে দেয়। আমরা বাধ্য হই, নিজস্ব তহবিল থেকে অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি শেষ করতে।

এছাড়াও বিভিন্ন কর বাবদ কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য সরকার যে অর্থ পায়, নানা সেস এবং সারচার্জ বসিয়ে তা যে ফেরত নিয়ে নিচ্ছে, সে কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এখন আবার কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কর কমিয়ে অতিরিক্ত সেস এবং সারচার্জ বসানোর। এতে আরও ক্ষতি হবে রাজ্যের। কমিশনের কাছে আমাদের আর্জি, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে কেন্দ্রকে এহেন প্রবণতা থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সুপারিশ করুন। এরই সঙ্গে রাজ্যের গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিতে যাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, কমিশনের কাছে সেই অনুরোধও জানানো হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে কর বাবদ আদায় করা অর্থের ৪২ শতাংশ এখন রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করে দেয় কেন্দ্র। সেই নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জোটে সব ৭.৩২ শতাংশ অর্থ। রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রের সেই বরাদ্দ কমপক্ষে ৫০ শতাংশ করার দাবি দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলের নেতারা ওই দাবি জানিয়েছিলেন। কমিশনকে দেওয়া স্মারকলিপিতে ফের সেই দাবি জানিয়েছে রাজ্য। এর পাশাপাশি রাজস্ব ঘাটতি বাবদ ৯০,১৩৬.৪৮ কোটি, পরিকাঠামো উন্নয়নের সাহায্য বাবদ ১,৪৬,৬৯২.৯৩ কোটি এবং প্রশাসনিক সংস্কার বাবদ ২৫,৮৩০.০১ কোটি টাকা অনুদান চেয়েছে রাজ্য। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য ৫,১৩৮ কোটি, জল ও বন সংরক্ষণের জন্য ২,৩৬৮ কোটি, পঞ্চায়েতের জন্য ৪২,৩১৯ কোটি এবং পুরসভাগুলির জন্য ২২ হাজার কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে।

• মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব চিত্র।

> আমরা বিশাল ঋণের বোঝা নিয়ে সরকারের কাজ শুরু করি। সেই ঋণ থেকে মুক্তি পেতে ঋণ পরিশোধের পরিকাঠামো পরিবর্তন করার দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও সদর্থক উত্তর পাইনি।
>
> —মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রী

> রাজ্যের উপর চেপে বসা বিপুল ঋণের বোঝা কীভাবে কমানো যেতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে।
>
> —এন কে সিং, অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান

Mamata becomes vocal against Centre's deprivation to State in front of Finance Commission. (Bartaman, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Bartaman
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18

রাজ্য সরকারের দরাজ প্রশংসা অর্থ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, চর্মশিল্প, নগর পরিকল্পনায় রাজ্যের কাজে খুশি পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়েই রাজ্যের কাজের প্রশংসা করেন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিং। তিনি বলেন, আমরা চার-পাঁচটি বিষয়ে খতিয়ে দেখেছি, রাজ্যের উন্নতি ভালো হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। সেই সঙ্গে আর্থিক সংস্কারে যেভাবে রাজ্য সরকার কাজ করছে, তা প্রশংসনীয়। রাজ্যে একাধিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার খুব ভালো। সামাজিক পরিষেবামূলক কাজেও রাজ্যে খুব ভালো করেছে। অর্থ কমিশনের প্রশংসায় যারপরনাই খুশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

পরে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বলেন, আমরা কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। খুবই অর্থবহ আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের প্রতি বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী শুরুতেই ২০১১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি ধরায় আপত্তি জানান। সেই সঙ্গে তুলে ধরেন প্রায় দু'লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়ে সাত বছর আগের সরকার শুরুর অভিজ্ঞতা। তিনি জানিয়ে দেন, ২০১১ সালের আগে রাজ্যে বন্‌ধ, ঘেরাওয়ের রাজনীতি ছিল। তা আজ অতীত। ২০১০-১১ আর্থিক বছরে রাজস্ব আদায় ছিল ২১,২১৮ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ সালে তা বাড়িয়ে

করা হয়েছে ৫২,৩৮৯ কোটি টাকা। আমরা বিশেষ নজর দিয়েছি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, কর্মসংস্থান, রাস্তা, সেতু, বিদ্যুতের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে। এর মধ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা দিয়ে পরিকাঠামো তহবিল তৈরি করা হয়েছে। যা দিয়ে রাস্তা, সেতু তৈরি হচ্ছে। নারী ও শিশু কল্যাণে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের উন্নয়ন এবং আর্থিক সংস্কার নিয়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সামনে দুটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তুলে ধরা হয়। যা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন অর্থ কমিশনের সদস্যরা। এন কে সিংয়ের নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রাক্তন অর্থসচিব শক্তিকান্ত দাস, ডঃ অনুপ সিং, অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক লাহিড়ি, ডঃ রমেশ চাঁদ। কমিশনের সচিব হলেন অরবিন্দ মেহতা। তাঁরা ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ সালের জন্য রাজ্যকে আর্থিক বরাদ্দের সুপারিশ করবেন। কোন রাজ্যকে কত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত, তার প্রস্তাব সম্বলিত রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দেবে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। তাঁদের সামনেই কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজসাথী, শিক্ষাশ্রী, গতিধারা, স্বাস্থ্যসাথী, সমব্যথী প্রকল্প তুলে ধরা হয়। এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে কত মানুষ উপকৃত হচ্ছে, তাও ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, এই ধরণের কাজে তিনি খুশি। তিনি বলেন, মানুষের কাছে সরাসরি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ ভালো। যেভাবে ই-পেমেন্ট বা ই-বিল চালু হয়েছে, তা খুবই প্রশংসার। তবে এসজিডিপি নিয়ে রাজ্যের দেওয়া হিসেবের সঙ্গে সেন্ট্রাল স্ট্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন (সিএসএসও)'র হিসেব মিলছে না এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আগামী মাসের মধ্যে সিএসএসও'র সঙ্গে আলোচনা করে এসজিডিপি সংক্রান্ত হিসেব চূড়ান্ত করা হবে।

এই একটি ক্ষেত্রে মতপার্থক্য ছাড়া এদিন অর্থ কমিশন দরাজ হাতে রাজ্যের কাজের প্রশংসা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে যে রাজ্যে অর্থনীতির পরিবর্তন হতে চলেছে তাও বুঝিয়ে দেন এন কে সিং। পরে বিকেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এন কে সিং। মমতা তখন নবান্ন থেকে বেরিয়ে হুচ্ছিলেন। মমতা তাঁকে তাঁর গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করেন। অনুরোধ মেনে তাঁর গাড়িতে করেই নবান্ন থেকে বেরিয়ে যান এন কে সিং। মমতা যান এক শিল্পপতির মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আজ, বুধবার কমিশনের সদস্য মধ্যমগ্রাম, নিউটাউনে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। -নিজস্ব চিত্র

Finance Commission widely praises WB Government. (Bartaman, Bengali, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

2

Name of Newspaper :- Sambad Pratidin
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 18-7-18

মানল অর্থ কমিশন

ঋণের বোঝা লাঘবের দাবি ন্যায্য

নবান্নে অর্থ কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার। —অমিত মোষ

স্টাফ রিপোর্টার : ঋণের চাপে দমবন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারকে বাঁচাতে ইতিবাচক পদক্ষেপ করা উচিত। সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে চাই বাড়তি অর্থ। রাজ্য সে ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছে, ফলে বাড়তি বরাদ্দের সুপারিশ করা যেতেই পারে। সরকারের সঙ্গে বৈঠক করে এবং সবদিক খতিয়ে দেখে এমনই ইঙ্গিত কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান নন্দকিশোর সিং জানিয়ে দিয়েছেন, "ঋণ পরিশোধের বিষয়টি পুনর্বিন্যাসের জন্য ভেবে দেখা দরকার। সে ব্যাপারে রাজ্য আর্জি জানিয়েছে। কমিশন রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবে।" গত কয়েক বছরে রাজস্ব আদায়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান-সহ বহু ক্ষেত্রে রাজ্যের কাজের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। সেই প্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে আর্থিক বঞ্চনা অনেকটাই কমবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বৈঠক খুব ভাল হয়েছে। ঋণকাঠামোর পুনর্গঠন নিয়ে দাবি জানিয়েছে রাজ্য। সব সেক্টর নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করি, ওঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। আরও আলোচনা চলবে। এন কে সিংজি ও সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন।

সোমবার থেকেই নানা ক্ষেত্র ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছে কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সদস্যরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয় তাঁদের। পরে এন কে সিং ক্ষেত্র তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকারের কাজের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলার সরকার গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে রাজস্ব ও কর আদায় বাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের মতো মানবসম্পদে জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুতেও উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। তাঁর বক্তব্য, "কমিশন প্রত্যক্ষ কর আদায় ও ই-বিলের মতো সিদ্ধান্তকে প্রশংসা করছে। দীর্ঘ মেয়াদে এর আরও আগের সরকারের সুফল মিলবে।" বাম সরকারের দেনার বিষয়ও মাথায় রাখছে কমিশন। রাজ্যও বিষয়টিতে জোর দিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, "প্রত্যেক ক্ষেত্রে সিরিয়াস নোট নেওয়া হয়েছে। যতটা সম্ভব তা করা হবে।" তিন দেশের সীমান্ত রাজ্য বাংলার 'স্ট্র্যাটেজিক' অবস্থানের কারণে গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েই এন কে সিং উল্লেখ করেন, পরবর্তী সময়ে বাংলা আরও এগিয়ে যেতে পারবে। মমতার নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রশ্নে তিনি বলেন, "কর্মসংস্থান তৈরির কাজ প্রশংসনীয়। অন্য রাজ্যের কাছে এটা নজির। এমনিতেই বাংলার মেধা ও দক্ষতা অতুলনীয়। তথ্য-প্রযুক্তি ও চর্মশিল্পের উন্নতির বিষয়টিও নজরে এসেছে।"

পাঁচের পাতায়

ঋণের বোঝা লাঘবের

একের পাতার পর

সোমবারই বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সুপারিশের কথা উল্লেখ করেন চেয়ারম্যান। সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনের সদস্য শক্তিকান্ত দাস ছাড়াও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, মুখ্যসচিব মলয় দে উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠন এবং পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির জন্য বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় যেভাবে ক্ষতি হয়েছে, তা নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্য। বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করতে ২৬৫০ কোটি টাকার মতো রাজ্যের নিজস্ব কোষাগার থেকে খরচ করতে হয়েছে। রাজ্য চাইছে, কেন্দ্রের টাকা রাজ্যগুলির মধ্যে ৫০ শতাংশ বণ্টন করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রিপোর্টের বিষয়ে রাজ্য সরকারের তরফে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বাম জমানার ঋণের বোঝার উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের কাছে বলেছেন, গত সাত বছরে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার দেনা ছাড়াও ঘেরাও, বন্‌ধের সংস্কৃতি, খারাপ কর্মসংস্কৃতি, জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন। গত সাত বছরে রাজ্য সরকার সুদ ও আসল সমেত প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা শোধ করতে হয়েছে। চলতি বছরে দিতে হচ্ছে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে সরকারকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার মধ্যে ২০১০-১১ সালের তুলনায় রাজস্ব আদায় দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। ওই আর্থিক বছরে রাজস্ব আদায় ছিল ২১২১৮ কোটি টাকা, গত আর্থিক বছরে হয়েছে প্রায় ৫২ হাজার ৩৮১ কোটি টাকা। জিএসটি চালুর পরও সারা দেশের নিরিখে রাজস্ব আদায়ের ব্যবধান কমিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মোট উৎপাদনের শতাংশের নিরিখে রাজস্ব ঘাটতিও কমেছে। তাঁর নেতৃত্বে সরকার যেভাবে সম্পদ তৈরিতে নজর দিয়েছে, সে ব্যাপারেও নির্দিষ্ট তথ্য-সহ রিপোর্ট দিয়েছে রাজ্য। মমতা উল্লেখ করেছেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, কর্মসংস্থান বা পরিকাঠামো তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ সরকারের কোনও না কোনও প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজসাথী, শিক্ষাশ্রী, গতিধারার মতো প্রকল্পের উল্লেখ রয়েছে রাজ্যের রিপোর্টে। জিএসডিপি-র মধ্যে মোট মূলধনী ব্যয় ২০১০-১১ সালের তুলনায় প্রায় চারগুণ হয়েছে। রাজ্যের বক্তব্য, ১৪তম অর্থ কমিশনের ৩২ থেকে ৪২ শতাংশে বণ্টন আসলে লোকদেখানো ছিল। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু না করার আর্জি রয়েছে।

The demand of minimising the burden of loan quite plausible. (Sangbad Pratidin, Bengali, 18.7.18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- The Telegraph
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :- 17/7/18

N.K. Singh in Calcutta on Monday. A Telegraph picture

Finance panel to exercise balance

A STAFF REPORTER

Calcutta: The 15th Finance Commission will exercise a balance between rewarding the performance of states and recognising the need for equity while deciding on the horizontal distribution of revenue among states.

The terms of reference of the commission mandate it to use population data from the 2011 census while making its recommendations and this has led to several states, especially in the south, voicing concern that they could lose distributed revenue compared to other states where population growth has been more.

However, commission chairman N.K. Singh on Monday said that while the terms of the commission called for the use of 2011, there is no restriction on the kind of weightage that could be given to the population parameter.

"Right from 1952, population has been used as an important variable in deciding horizontal distribution. Of course weights given to population have varied. But, nothing in the terms of reference prevents this finance commission of according weights to population," said Singh at an Indian Chamber of Commerce organised session on Monday.

He added that while the commission will rely on the 2011 census, there is a provision in the terms that empowers the commission to incentivise those states that have achieved "good and rapid" progress on demographic management.

"It will be the endeavour of this commission to ensure that appropriate balance and fair judgement is reached between rewarding performance and recognising the need for equity," Singh said.

He also said that for the first time, the commission has been mandated according to the terms of reference to lay down the conditions that the Centre will impose while providing consent under Article 293(3) of the Constitution.

The article states that a state may not without the consent of the central government raise any loan if there is still outstanding any part of a loan, which has been made to the state by the Centre or by its predecessor government, or in respect of which a guarantee has been given by the Centre or by its predecessor government.

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :-
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
Date of Publication :-

जनसंख्या प्रबन्धन : 'अच्छी और तेज' प्रगति वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगा वित्त आयोग : एन. के. सिंह

15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन. के. सिंह का स्वागत करते डॉ. राजीव सिंह

कोलकाता : 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एन. के. सिंह ने कहा कि वित्त आयोग उन राज्यों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर सकता है जिन्होंने जनसंख्या प्रबन्धन में 'अच्छी और तेज' प्रगति की है। उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल ने जनसंख्या प्रबंधन में 'अच्छी और तेज' प्रगति की है। बंगाल जैसे तेज प्रगति करने वाले राज्यों को प्रोत्याहित करने पर वित्त आयोग विचार करेगा। वे इस दिन इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा यहाँ आयोजित एक परिचर्चा सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। सिंह ने कहा कि दक्षिण भारत में जनसंख्या गिरावट वाले कई राज्यों ने वित्त आयोग द्वारा राज्यों को प्रत्साहित करने के लिए साल 1972 की जनगणना की जगह पर साल 2011 की जनगणना को चुनने का विरोध किया है क्योंकि 14 वें वित्त आयोग में साल 1972 और 2011 की जनसंख्या के आँकड़े, दोनों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के स्थिरकरण के काम को भी महत्व दिया जाना चाहिये। सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किये गये कार्यों पर सन्तोष जताया लेकिन अधिक कर्ज लेने पर चिन्ता जतायी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत यह नियम बना सकती है कि केन्द्र सरकार से अनुमति लिये बगैर कोई भी राज्य कर्ज नहीं ले सकेगा। इस प्रस्ताव पर भी वित्त आयोग विचार करेगा। सिंह ने कहा कि 15वाँ वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 तक सौंपेगा। आयोग केन्द्र व राज्य सरकारों के वित्तीय घाटे, कर्ज स्तर और राजकोषीय अनुशासनों प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा। इस अवसर पर आईसीसी के महानिदेशक डॉ. राजीव सिंह ने स्वागत भाषण दिया।

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

Name of Newspaper :- Aaj Kal
Language :- ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU
Place of Publication :- Kolkata (West Bengal)
17/7/18

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একমত বাম-কং

রাজ্যের থেকে নেওয়া টাকার ৫০% ফেরত দেওয়ার দাবি

আজকালের প্রতিবেদন

কর আদায়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একই দাবিতে দাঁড় করিয়ে দিল বাংলার সব রাজনৈতিক দলগুলিকে। কর বাবদ কেন্দ্রের দেয় অর্থের পরিমাণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করার দাবি উঠল পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বৈঠকে। আর এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সুরেই এই দাবিতে সরব হলেন বিজেপি ছাড়া সব রাজনৈতিক দলেরই প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি অর্থ কমিশন রাজ্যের বেশ কিছু জনমুখী উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপারে প্রশংসাও করেছে এদিনের বৈঠকে।

প্রসঙ্গত, মমতা দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যগুলির প্রতি এই খাতে বঞ্চনার অভিযোগ তুলছেন মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। কেন্দ্র রাজস্ব আদায় বাবদ কোটি কোটি টাকা কেটে নেয় সব রাজ্যের কাছে। বিভিন্ন খাতে যে কর আদায় করে, তার সামান্য অংশ উন্নয়নে খরচ করতে ফেরত দেয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বহুবার এই আর্থিক নীতির বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন। তাঁর দাবি, এই টাকা আরও বাড়াতে হবে। সোমবার অর্থ কমিশনের ওই বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও সেই একই দাবিতে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। সেইসঙ্গে বেশ কিছু জনমুখী প্রকল্পে বিশেষ প্যাকেজের দাবিও তোলা হয়।

এদিন নবান্নের সভাঘরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বৈঠক বসে। তার আগে অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান নন্দকিশোর সিং-সহ ৬ সদস্যকে অভ্যর্থনা জানান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ও রাজ্যের অর্থ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকেরাও ছিলেন। আর কমিশনের সদস্যরা হলেন— শক্তিকান্ত দাস, অনুপ সিং, রমেশ চাঁদ ও সচিব অরবিন্দ মেহেতা।

প্রসঙ্গত, দেশে প্রতি ৫ বছর পরপর এই অর্থ কমিশন গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে সব খাতে কর নেয় রাজ্যগুলির কাছ থেকে, তার কত শতাংশ ফেরত দেওয়া উচিত এবং কীসের ভিত্তিতে— এ সব বিষয়ই উঠে আসে আলোচনায়। বৈঠকে শুধু সরকারের প্রতিনিধিরা নন, তৃণমূল, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, বিজেপি-র প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এছাড়াও সব জেলা সভাধিপতি, পুরসভার মেয়র প্রমুখ। প্রথম দিনের এই বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন পার্থ চ্যাটার্জি, ফিরহাদ হাকিম, কলকাতার মেয়র শোভন চ্যাটার্জি। বাম প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত। এছাড়াও ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, আরএসপি-র সুভাষ নস্কর, ফব-র হাফিজ আলম সাইরানি, এনসিপি-র রাজ্য সভাপতি প্রবোধচন্দ্র সিনহা, সিপিআইয়ের রাজ্য সম্পাদক স্বপন ব্যানার্জি। কংগ্রেসের তরফে ছিলেন নেপাল মাহাতো, বিজেপি-র পঙ্কজ রায়।

অর্থ কমিশনের কর্তা এন কে সিং

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বৈঠকে পার্থ চ্যাটার্জি ও ড. অসীম দাশগুপ্ত। নবান্নে। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

এদিকে, বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের কাছে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত বলেন, 'রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ৬১ শতাংশ অর্থ সব রাজ্য থেকে নিয়ে নেয়। এই বিষয়টি তুলে ধরেছি আমরা।'

উল্লেখ্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব বলছে, ২০১৬-১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ৮.৯ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করছে। সেখানে রাজ্য সরকারগুলি খরচ করেছে ১৯.৮ লক্ষ কোটি টাকা। কেন্দ্র-রাজ্য মিলে রাজস্ব আদায়ের ৬১ শতাংশ চলে যায় কেন্দ্রীয় কোষাগারে। সেখানে রাজ্যকে দেয় অর্থের পরিমাণ ৩২ থেকে বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ করা হয়েছে। বৈঠকে সবার দাবি, এটা ৫০ শতাংশ করতেই হবে। জিএসটি, কর আদায়ে সরলীকরণ থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রতিরোধ করা দরকার সে-বিষয়েও অর্থ কমিশনের কাছে বলেছেন বাম প্রতিনিধিরা। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের পর বিভিন্ন পুরসভা, জেলা সভাধিপতি, পঞ্চায়েতের সদস্যদের কথাও শোনে অর্থ কমিশন। বক্তব্য পেশ করেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র সব্যসাচী দত্ত, বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরি, মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান রথীন ঘোষ, কান্দি পুরসভার চেয়ারম্যান অপূর্ব সরকার, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগরওয়াল, জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মজরুল ইসলাম প্রমুখ। এদিকে, আজ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বৈঠকে বসছে অর্থ কমিশনের ওই প্রতিনিধিদল। এদিন সন্ধেয় কমিশনের চেয়ারম্যান নন্দকিশোর সিং ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের এক আলোচনাসভাতেও যোগ দেন।

Demand to return 50 percent of the finances taken from the state – Left and Congress agrees with West Bengal CM. (Aajkal/17/7/18)

PRESS INFORMATION BUREAU
GOVERNMENT OF INDIA
KOLKATA
*****

(2)

Name of Newspaper	:-	Sambad pratidin
Language	:-	**ENGLISH/BENGALI/HINDI/URDU**
Place of Publication	:-	**Kolkata (West Bengal)**
Date of Publication	:-	17/7/18

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে চেয়ারম্যান এন কে সিং

কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনে রাজ্যের সুরেই বিরোধীরা

স্টাফ রিপোর্টার : কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের কাছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই বাংলার হয়ে দাবি জানাল বাম-কংগ্রেস। কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার বিরোধিতার পাশাপাশি তাঁরাও প্রশ্ন তুলেছেন, জনমুখী প্রকল্প কেন বন্ধ করে দেওয়া হবে? রাজ্যের মোট উৎপাদন বা স্টেট জিডিপি-র ভিত্তিতেই কেন্দ্র টাকা বণ্টন করুক, চেয়েছে সিপিএমও। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান। অর্থ-বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার আগে বহু ইস্যুতে বাম ও কংগ্রেসকে পাশে পাওয়া নিঃসন্দেহে রাজ্যের কাছে 'অ্যাডভান্টেজ'। বিভিন্নস্তরে রাজ্যের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পরই অর্থ কমিশনের বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কমিশন। সোমবারই ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের এক আলোচনাসভায় যোগ দিয়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান নন্দকিশোর সিং বলেন, "রাজ্যের অনেকগুলি দাবি রয়েছে। তার কিছু যৌক্তিকতা রয়েছে। ভেবে দেখা হবে।"

এদিন এন কে সিং-এর কাছে বামেরা যেমন রাজ্য থেকে কর আদায়ে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধির দাবি করেছে, তেমনই কংগ্রেস চেয়েছে বাংলার জন্য বিশেষ প্যাকেজ। অর্থ বরাদ্দে কেন্দ্রের বঞ্চনায়ও বাম-কংগ্রেসের সুর প্রায় এক। কেন্দ্রের শেয়ার বাড়ানো হোক, দাবি তুলেছেন বিরোধীরা। রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত বলেন, কেন্দ্রের উচিত ঋণ

কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিং।

পরিকাঠামো পুনর্গঠন করা। ডিভিসি-সহ রাজ্যের নদী সংস্কারের উপরও জোর দিয়েছেন তিনি। তেমনই বামফ্রন্টের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন, রাজ্যের থেকে কেন্দ্র যে কর আদায় করে, তার ৫০ ভাগ কেন রাজ্যকে দেওয়া হবে না। কংগ্রেসের বিধায়ক নেপাল মাহাতো দাবি তোলেন, রাজ্যের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিতে হবে। ইউপিএ সরকারের সময়ে জঙ্গলমহলের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য যেমন বিশেষ প্যাকেজ বা বাড়তি বরাদ্দ ছিল, সেই ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবিও রয়েছে। উল্লেখ্য, মমতা নিজেও বারবার কেন্দ্রের কাছে এই দাবিগুলিতে সরব হয়েছেন। চিঠি লিখে বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য আদায় বন্ধ করার প্রতিবাদ করেছিলেন। এবার বিজেপি বাদে সিপিএম, কংগ্রেস ও অন্য বিরোধী দলগুলিকেও পাশে পেলেন মমতা। সোমবার সকাল থেকেই নবান্ন সভাঘরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে মতামত শোনেন কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের সদস্যরা। এন কে সিং-সহ কমিশনের ১৫ সদস্য এসেছেন রাজ্যের অর্থ বরাদ্দ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। দলে রয়েছেন শক্তিকান্ত দাস, অনুপ সিং, অশোক লাহিড়ি, রমেশ চাঁদ, সচিব অরবিন্দ মেহতা। বুধবার পুরসভা ও পঞ্চায়েতের কাজ সরেজমিনে ঘুরে দেখবেন কমিশনের সদস্যরা। তার আগে কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও মধ্যমগ্রাম, কান্দি, জঙ্গিপুর, ইসলামপুর, বারুইপুর-সহ কয়েকটি পুরসভার প্রধানের সঙ্গেও কথা বলেন। ছিলেন বিভিন্ন জেলা পরিষদের সভাধিপতিরা।

অসীমবাবু ছাড়াও বামেদের প্রতিনিধিদলে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, সিপিআইয়ের স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, আরএসপির সুভাষ নস্কর, ফরওয়ার্ড ব্লকের বরুণ মুখোপাধ্যায়, হাফিজ আলম সাইরানি প্রমুখ। বিজেপির পক্ষে ছিলেন পঙ্কজ রায়। মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিমও রাজ্যের তরফে বেশ কিছু দাবি পেশ করেন। এদিন শুরুতে এন কে সিংকে স্বাগত জানান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। অসীমবাবু আবার পরে সাংবাদিকদের বলেন, "বাম জমানার শেষের দিকে এক লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা ঋণ ছিল। স্বল্পসঞ্চয়ের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল। পরে কেন্দ্র তা ঋণ হিসাবে ধরে। এ নিয়ে আমাদের আপত্তি ছিল। এখন যা নেওয়া হচ্ছে বেশিটাই বাজার থেকে নেওয়া। ঋণের কাঠামো পুনর্গঠন করতে হবে।"

Opposition in Bengal speaks in the same tune as ruling party in their discussions with finance commission – Chairman N.K. Singh to meet CM today. (Sangbad Pratidin/17/7/18).